



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1060]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जून 2, 2011/ज्येष्ठ 12, 1933

No. 1060]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 2, 2011/JYAISTHA 12, 1933

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2011

का.आ. 1268(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(4) के अनुसरण में माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव सहाय एन्डलॉ, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय, जिन्हें मेघालय के हनीवट्रेप लिब्रेशन काउन्सिल (एच एन एल सी) नामक संगठन को विधिविरुद्ध घोषित किए जाने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान होने अथवा न होने के संबंध में न्याय निर्णयन के लिए विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(1) के अंतर्गत एक संदर्भ भेजा गया था, की अध्यक्षता में गठित अधिकरण के आदेश को आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

[फा. सं. 11011/56/2010-एन ई. III]

शम्भू सिंह, संयुक्त सचिव

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव सहाय एन्डलॉ, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता में गठित विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण के समक्ष के संदर्भ में :

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3(1) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेघालय के हनीवट्रेप लिब्रेशन काउन्सिल को विधिविरुद्ध संगठ घोषित किए जाने के बारे में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी की गई दिनांक 16 नवम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 2792(अ)

आदेश

13-5-2011

1. विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (जिसे इसमें इसके पश्चात्

अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 (1) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई दिनांक 16 नवम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 2792 (अ) के द्वारा केन्द्र सरकार ने यह घोषणा की कि उसकी यह राय है कि मेघालय का हन्नीवट्रेप नेशनल लिब्रेशन काउन्सिल (जिसे इसमें इसके पश्चात एच एन एल सी कहा गया है), इसके सभी गुटों, विंगों और प्रमुख संगठनों सहित, विधिविरुद्ध संगम हैं। अधिसूचना जारी किए जाने के संबंध में, अधिनियम की धारा 3 (2) के अर्थ के भीतर अधिसूचना में यथानिर्धारित आधार निम्न प्रकार हैं:

क. कि एच एन एल सी:

- i) मेघालय राज्य के भारत संघ से पृथक्करण के उद्देश्य की घोषणा करता रहा है;
- ii) अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए सशस्त्र साधनों का प्रयोग कर रहा है तथा उनमें लिप्त बना हुआ है;
- iii) अपने संगठन के लिए निधियां इकट्ठी करने के लिए डराने-धमकाने तथा जबरन धन वसूली के कार्यों में लिप्त रहा है;
- iv) जबरन धन वसूली करने और डराने-धमकाने की कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए पूर्वोक्त क्षेत्र के अन्य उग्रवादी संगठनों के साथ संपर्क बनाए हुए है;
- v) शरण स्थल अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजन से कुछ पड़ोसी देशों में शिविर बनाए हुए हैं; और
- vi) भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकार है;

ख. कि यदि एच एन एल सी की गतिविधियों पर तत्काल अंकुश नहीं लगाया गया तथा इन्हें नियंत्रित नहीं किया गया तो एच एन एल सी अपने को फिर से संगठित तथा शस्त्रों से लैस कर लेगा, अपने काइरों का विस्तार करेगा, अत्याधुनिक हथियार प्राप्त करेगा, नागरिकों और सुरक्षा बलों की हत्या करेगा तथा अपनी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को तेज करेगा;

ग. कि एच एन एल सी को, इसके सभी गुटों, विंगों तथा प्रमुख संगठनों सहित, तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित करना आवश्यक है।

2. एच एन एल सी को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान होने अथवा न होने के बारे में न्याय निर्णयन करने के प्रयोजन से अधिनियम की धारा 5 (1) के अनुसरण में, दिनांक 13 दिसम्बर, 2010 की दूसरी अधिसूचना सं. का. आ. 2934 (अ) के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को शामिल करते हुए अधिकरण का गठन किया गया था।

3. उक्त अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत श्री आर आर झा, संयुक्त सचिव, (एन ई-11) गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 21 दिसम्बर, 2010 के पत्र संख्या 11011/56/2010-एन ई.111 के तहत 21 दिसम्बर, 2010 को धारा 3(1) (सुप्रा) के अंतर्गत अधिसूचना के संदर्भ और उक्त दो अधिसूचनाएं और एच एन एल सी के उद्देश्य/लक्ष्यों और हिंसक गतिविधियों के बारे में संक्षिप्त सार अधिकरण को भेजा गया था। अधिकरण के रजिस्ट्रार ने 23 दिसम्बर, 2010 को, जब भारत संघ की ओर से ए.एस. चंडोक, विद्वान एडीशनल सॉलिसीटर जनरल और मेघालय राज्य की ओर से अधिवक्ता श्री रंजन मुखर्जी भी उपस्थित हुए थे, उक्त दस्तावेजों को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

4. 23 दिसम्बर, 2010 को, उक्त अधिनियम की धारा 4(2) के अंतर्गत एच एन एल सी को 30 दिन के अन्दर कारण बताओ संबंधी नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया कि इसे विधिविरुद्ध क्यों न घोषित किया जाए। एच एन एल सी को उक्त नोटिस निम्न प्रकार तामील किए जाने का निदेश दिया गया - i) एच एन एल सी के कार्यालय (कार्यालयों), यदि कोई हो, के प्रमुख भागों पर अधिसूचना की प्रति चिपकाकर; ii) जहां कहीं संभव हो, एच एन एल सी के मुख्य पदाधिकारियों को अधिसूचना की प्रति की तामीली के द्वारा; iii) एच एन एल सी की गतिविधियां सामान्य रूप से चलाए जाने वाले क्षेत्र में ढोल बजाकर अथवा लाउडस्पीकों के द्वारा अधिसूचना की विषय-वस्तु की उदघोषणा करके; iv) आकाशवाणी के स्थानीय अथवा निकटतम प्रसारण केन्द्र से रेडियो पर उदघोषणा करके; v) मेघालय राज्य में सात जिलों में से प्रत्येक जिले के मुख्यालय में उपायुक्तों के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर अधिसूचना को चिपकाकर; और vi) अंग्रेजी के राष्ट्रीय समाचार पत्र में और संबंधित राज्यों, जिनमें एच एन एल सी की गतिविधियां सामान्य रूप से चलाई जाती हैं, के स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन के द्वारा। केन्द्र सरकार को नोटिस की तामीली के संबंध में आवश्यक और पर्याप्त प्रबंध करने का निदेश दिया गया था। उक्त नोटिस अधिकरण के रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से 28 जनवरी, 2011 को अपराह्न 4.00 बजे जारी किया गया।

5. श्री शम्भू सिंह, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने, जारी किए गए उक्त नोटिस की निदेशानुसार विभिन्न तरीकों से तामीली की बात की पुष्टि करते हुए दिनांक 27 जनवरी, 2011 का एक शपथपत्र दायर किया। इस शपथ पत्र के अनुसार, दिनांक 16 नवम्बर, 2010 की अधिसूचना (सुप्रा) अधिनियम की धारा 3 (4) के अनुसरण में आगे की कार्रवाई करने के लिए मुख्य सचिव, मेघालय सरकार को अग्रेषित कर दी गई थी; कि अधिसूचना मेघालय राज्य के राजपत्र में पुनः प्रकाशित की गई और तत्पश्चात कुछ स्थानीय समाचारपत्रों में भी प्रकाशित की गई; उक्त नोटिस की तामीली 8 जनवरी, 2011 को स्थानीय समाचारपत्रों में प्रकाशन के द्वारा, आकाशवाणी से प्रसारण के द्वारा, दूरदर्शन केन्द्र, शिलांग के माध्यम से प्रसारण के द्वारा और राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले, रि भोई जिले, नोन्गपाँह, पश्चिम खासी हिल्स जिले और पूर्वी गारो हिल्स, विलियमनगर के उपायुक्तों के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकाकर/लटकाकर भी की गई।

6. 28 जनवरी, 2011 को, उपर्युक्तानुसार नोटिस की तामीली के बारे में प्रस्तुत सामग्री के आधार पर मैं इस बात से संतुष्ट था कि नोटिस की विधिवत रूप से तामीली कर दी गई थी। तथापि, एच एन एल सी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। भारत संघ के विद्वान ए एस जी तथा मेघालय राज्य के वकील ने शपथपत्रों के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा जिसकी अनुमति प्रदान कर दी गई तथा इस मामले को विचार किए जाने के लिए दिल्ली में 17 फरवरी, 2011 तक स्थगित कर दिया गया। मेघालय राज्य के वकील के इस सुझाव पर कि स्थानीय लोगों की भागीदारी, यदि कोई हो, की अनुमति देने के लिए गवाहों से पूछताछ शिलांग में की जाए, गवाहों से पूछताछ 25 और 26 फरवरी, 2011 को होटल पाइन वुड, शिलांग में प्रातः 10.30 बजे के लिए निर्धारित की गई। राज्य के वकील को पूर्व में निदेशानुसार सभी साधनों से सुनवाई के समय और स्थान को प्रकाशित करने का निदेश दिया गया ताकि यदि स्थानीय लोग चाहें तो वे इसमें भाग ले सकें।

7. 17 फरवरी, 2011 को राज्य के वकील ने, सुनवाई के समय और स्थान के प्रकाशन से संबंधित निदेशों की अनुपालना के बारे में श्री बी.धर, सचिव, मेघालय सरकार, राजनैतिक विभाग, शिलांग, मेघालय का एक शपथपत्र प्रस्तुत किया। मैरिट के आधार पर भी एक शपथपत्र प्रस्तुत किया गया और अनुरोध किए जाने पर शेष शपथपत्र प्रस्तुत करने का समय 25 फरवरी, 2011 तक बढ़ा दिया गया। राज्य के वकील ने यह भी सूचित किया कि कुछ अत्यावश्यकताओं के कारण होटल पाइन वुड, शिलांग 25 और 26 फरवरी, 2011 को सुनवाई के लिए उपलब्ध

नहीं था। तदनुसार, सुनवाई का स्थान बदलकर होटल पोलो टॉवर, शिलांग कर दिया गया और पूर्व में यथा आदेशित तरीके से सुनवाई के स्थान में परिवर्तन को अधिसूचित किए जाने के संबंध में निदेश जारी किया गया।

8. अधिकरण की अगली सुनवाई यथा आदेशित 25 फरवरी, 2011 को शिलांग में हुई। राज्य सरकार के वकील ने सूचित किया कि सुनवाई के स्थान में परिवर्तन को निदेशानुसार प्रकाशित किया गया था तथा अनुपालन संबंधी शपथपत्र अगली तारीख अर्थात् 26 फरवरी, 2011 को प्रस्तुत करने का समय मांगा गया। एच एन एल सी की ओर से 25 और 26 फरवरी, 2011 को भी कोई उपस्थित नहीं हुआ और एच एन एल सी को नोटिस जारी किए जाने से संतुष्ट होते हुए और इंतजार करने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई तथा राज्य के वकील को अपने गवाहों को पेश करने का निदेश दिया गया। वकील ने सूचित किया कि राज्य नौ गवाह पेश करना चाहता है।

9. 25 फरवरी, 2011 को हुई सुनवाई के दौरान राज्य के पाँच गवाहों से पूछताछ की गई तथा अन्य गवाहों से पूछताछ करने के लिए इस मामले को 26 फरवरी, 2011 तक स्थगित कर दिया गया।

10. 26 फरवरी, 2011 को राज्य के वकील ने स्थान में परिवर्तन के नोटिस की तामीली के बारे में दिनांक 17 फरवरी, 2011 के आदेश की अनुपालना संबंधी शपथपत्र प्रस्तुत किया; राज्य के शेष चार गवाहों से पूछताछ की गई और मेघालय राज्य ने अपनी गवाही बंद कर दी। केन्द्र सरकार के वकील ने बताया कि केवल एक गवाह से पूछताछ की जानी थी तथा उक्त गवाह से दिल्ली में पूछताछ करने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी और तदनुसार शिलांग में कार्यवाहियां बंद कर दी गईं।

11. केन्द्र सरकार ने अपने गवाह के रूप में दिनांक 4 अप्रैल, 2011 को श्री जे.पी.एन. सिंह, निदेशक, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से पूछताछ की तथा अपने साक्ष्य समाप्त किए। तथापि, मेघालय राज्य ने अतिरिक्त गवाहों से पूछताछ करने की अनुमति मांगी तथा उन्हें यह अनुमति दी गई।

12. 25 अप्रैल, 2011 को मेघालय राज्य ने छह अतिरिक्त गवाहों से पूछताछ की तथा पुनः साक्ष्य समाप्त किए। दिनांक 29 अप्रैल, 2011, 2 मई, 2011, 4 मई, 2011 और 10 मई,

2011 को सुविज्ञ एडिशनल सॉलिसीटर जनरल तथा मेघालय राज्य से दलीलें सुनी गईं। इन कार्यवाहियों के दौरान एच एन एल सी अनुपस्थित रहा।

13. संदर्भ के साथ अग्रेषित संक्षिप्त सार के अनुसार :

क. एच एन एल सी का गठन, भारत सरकार के दमनकारी शासन से हन्नीवट्रेप लोगों (खासी और जैंतिया जनजातियों) को स्वतंत्र कराने, खासी तथा मेघालय की अन्य जनजातियों को शोषण से बचाने, स्वदेशी संस्कृति को बनाए रखने तथा सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के उद्देश्य से 1992 में किया गया था। इसका संकल्प खासी समाज को बांटने के लिए होने वाले किसी भी प्रयास के खिलाफ लड़ने का भी है।

ख. एच एन एल सी धमकाने तथा जबरन धन-वसूली में निरंतर संलिप्त है। 27 जनवरी, 2010 को मेघालय पुलिस ने मेघालय के वेस्ट खासी हिल्स जिले से 8 अन्य एच एन एल सी काडरों के साथ एच एन एल सी के एक दुर्दांत काडर एलेक्स हाशाह को गिरफ्तार किया। पुलिस ने संगठन के गिरफ्तार हुए काडरों से हथियार और गोलाबारूद जब्त किए। दिनांक 6 अप्रैल, 2010 को एच एन एल सी ने कून हुंडई, शिलांग के मालिक किम मरबनियांग से 30 लाख रु. की मांग की। दिनांक 7 मई, 2010 को सीमा सुरक्षा बल ने एच एन एल सी के स्वयं-भू सार्जेंट मेजर परिस्टन पकनेटिन को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान परिस्टन पकनेटिन ने यह स्वीकार किया कि उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 16 दिसम्बर, 2007 को फेरशल कांगवांग का अपहरण किया था और उसे बंगलादेश ले गए जहां उसकी हत्या कर दी गई। उसने यह बात भी स्वीकार की कि 22 फरवरी, 2009 को वह अपने सहयोगियों के साथ मावरियांग गांव गया था ताकि वह श्री ट्राप सुटिंग को सबक सीखा सके जिसने 31.1.2009 को संगठन द्वारा मांगी गई फिरौती की रकम देने से मना कर दिया है। श्री ट्राप सुटिंग के पुत्र श्री कुलार सुटिंग पर संगठन द्वारा गोली चलाई गई जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

ग. एच एन एल सी मेघालय में यूरेनियम की खुदाई का विरोध करता रहा है। 10 जनवरी, 2008 को संगठन ने घोषणा की कि वह यूरेनियम की खुदाई का समर्थन करने वाले किसी भी संगठन या व्यक्ति को नहीं छोड़ेगा क्योंकि यह अयस्क हन्नीवट्रेप लोगों की 'वैधानिक संपत्ति' है न कि भारत की। यह संगठन स्वतंत्रता दिवस के समारोहों का विरोध भी करता रहा है। इस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस, 2010 के समारोह के विरोध स्वरूप रि भोई जिले के खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स में 14 अगस्त, 2010 को सायं 6 बजे से 36 घंटों के बंद का आह्वान किया था।

इस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस के विरोध में 14 अगस्त, 2009 को भी 24 घंटों के बंद का आह्वान किया था।

घ. एच एन एल सी, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन डी एफ बी), नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (विश्वमोहन देबवर्मा) और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इसाक-मुइवाह) [एन एस सी एन (आई/एम)] के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। उपलब्ध सूचना के अनुसार इस संगठन के बंगलादेश में शिविर/आश्रय-स्थल हैं और इसके प्रमुख नेता, स्वयं-भू कमांडर-इन-चीफ बॉबी मरवीन और स्वयं-भू महासचिव चेरिस्टरफाइलेड थांगखिव बंगलादेश से निरंतर अपनी गतिविधियां चला रहे हैं।

ड. एच एन एल सी मुख्यतः मेघालय के खासी हिल्स में सक्रिय है। अनुमान है कि एच एन एल सी के लगभग 50 से 60 काडर हैं। ऐसा अनुमान है कि वर्तमान में संगठन के पास ए के श्रृंखला की राइफलें, लाईट मशीनगन और राइफलों सहित लगभग 20 हथियार मौजूद हैं।

च. उल्लिखित पैराओं में बताई गई एच एन एल सी की गतिविधियों की पृष्ठभूमि में एच एन एल सी को निम्नलिखित आधार पर 15 नवम्बर, 2010 से दो वर्ष की अवधि के लिए 'विधि-विरुद्ध संगम' घोषित किया गया था :

- (i) भारत से मेघालय राज्य के खासी और जैंतिया जनजाति बहुल क्षेत्रों को पृथक करने संबंधी एच एन एल सी का खुले तौर पर घोषित उद्देश्य;
- (ii) एच एन एल सी द्वारा अपने संगठन के लिए धनराशि एकत्र करने के लिए आम नागरिकों को लगातार धमकाया जाना और जबरन धनवसूली;
- (iii) जबरन धनवसूली और धमकाने जैसे कृत्यों को अंजाम देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य विद्रोही गुटों से संबंध बनाए रखना;
- (iv) सुरक्षित शरण-स्थली और अपने काडरों के प्रशिक्षण के उद्देश्य से बंगलादेश में शिविर बनाए रखना।

छ. एच एन एल सी की गतिविधियां जारी हैं और यह महसूस किया गया कि यदि अधिसूचना के विस्तार में किसी भी प्रकार का विलंब हुआ तो यह संगठन स्थिति का अनुचित लाभ उठाकर अलगाववाद, विध्वंसक और हिंसक गतिविधियां बढ़ाने के लिए अपने काडरों को एकजुट कर सकता है। इससे इस संगठन के नेताओं को यह अवसर मिल सकता है कि वह

भारत की सुरक्षा चिंताओं से विद्वेष रखने वाले विदेशी तत्वों के साथ मिलकर राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों का खुलेआम प्रचार कर सके। ऐसी परिस्थिति में पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए भी संगठन के सदस्यों या काइरों को नजरबंद करना और उन पर अभियोजन चलाना कठिन हो जाएगा। अतः यह आवश्यक समझा गया कि एच एन एल सी पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अधिसूचना को शासकीय राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की और अवधि के लिए विस्तारित किया जाए।

ज. मेघालय सरकार, रक्षा मंत्रालय, आसूचना ब्यूरो, मंत्रिमंडल सचिवालय (अनुसंधान एवं अन्वेषण विंग), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल ने भी एच एन एल सी को 'विधि-विरुद्ध संगम' के रूप में की गई घोषणा को जारी रखने की सिफारिश की है।

14. केन्द्र सरकार के एकमात्र गवाह ने बयान दिया है कि :

- क. भारत सरकार के निरंकुश शासन से हन्नीवट्रेप लोगों (खासी और जैतिया जनजाति) को मुक्त कराने के उद्देश्य से वर्ष 1992 में एच एन एल सी का गठन किया गया था;
- ख. वर्तमान में इसके संगठन-पदाधिकारी, श्री बॉबी मरवाइन (स्वयं-भू कमांडर-इन-चीफ) और श्री चेरिस्टरफाइलेड थंगखिव (स्वयं-भू महासचिव) हैं;
- ग. एच एन एल सी, राष्ट्रीयता को समाप्त करने तथा भारत संघ से मेघालय राज्य को पृथक करने संबंधी उद्देश्य के साथ कार्य कर रहा है;
- घ. इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एच एन एल सी सशस्त्र संघर्ष, आम नागरिकों को डराने-धमकाने और उनसे धनराशि ऐंठने में संलिप्त है;
- ङ. एच एन एल सी अन्य विधिविरुद्ध संगमों अर्थात् नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन डी एफ बी), नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एन एल एफ टी) तथा नागालैंड के एक उग्रवादी संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इसाक-मुईवाह) [एन एस सी एन (आई/एम)] के साथ भी संबंध बनाए हुए है;

- च. एच एन एल सी के शीर्ष नेता गिरफ्तारी से बचने के लिए बंगलादेश में शिविर/आश्रय-स्थल बनाए हुए हैं;
- छ. एच एन एल सी मेघालय में यह दावा करते हुए यूरेनियम की खुदाई का विरोध करता रहा है कि यह भारत की नहीं बल्कि हन्नीवट्रेप लोगों की संपत्ति है और इसमें शामिल लोगों को वे धमकाते हैं;
- ज. एच एन एल सी भारत के राष्ट्रीय दिवस (गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस) समारोहों का विरोध करता रहा है;
- झ. केन्द्र सरकार को आसूचना एजेंसियों और मेघालय राज्य सरकार से एच एन एल सी के विधि-विरुद्ध क्रियाकलापों और कार्यकर्ताओं के बारे में सूचना प्राप्त हुई है;
- ञ. ये रिपोर्टें/सूचनाएं महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रकृति की हैं और इन्हें एच एन एल सी अथवा किसी तीसरे पक्षकार को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है क्योंकि सरकार यह समझती है कि इन रिपोर्टों को सार्वजनिक करना जनहित के खिलाफ होगा;
- ट. इनकी गतिविधियां गुप्त प्रकृति की हैं और संगठन की विधिविरुद्ध गतिविधियों की सूचनाओं के स्रोत को भी परिणामतः गुप्त रखना आवश्यक है।

15. उक्त गवाह ने अपनी गवाही के दौरान एक सीलबंद लिफाफा सौंपा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी सूचना भी थी जिसके आधार पर दिनांक 16 नवम्बर, 2010 की अधिसूचना जारी की गई थी। उक्त सीलबंद लिफाफे को खोला गया और उसमें उपलब्ध सामग्री को पढ़ा गया। इसमें उक्त अधिनियम के विस्तार के भीतर विधिविरुद्ध संगम की गतिविधियों पर नजर रखने और अन्यथा भारत की अखंडता और संप्रभुता बनाए रखने के संबंध में अपनी आधिकारिक ड्यूटी के निष्पादन के दौरान विभिन्न पदाधिकारियों से अपेक्षित तथा चाही गई रिपोर्टें थी कि एच एन एल सी, एन एस सी एन (आई एम) को सक्रिय समर्थन दे रहा है और भारत सरकार के निरंकुश शासन से हन्नीवट्रेप अर्थात् राज्य के खासी और जैंतिया लोगों को स्वतंत्र कराने का लक्ष्य बनाए हुए है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से धनराशि एकत्र करने सहित राज्य के अन्य नागरिकों को निरंतर आतंकित किए हुए है। उक्त दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि एच एन एल सी धमकाता रहा है कि वह यूरेनियम की खुदाई नहीं करने देगा क्योंकि उसका

दावा है कि यह संपत्ति हन्नीवट्रेप लोगों की है न कि भारत की। ऐसी भी रिपोर्टें हैं कि एच एन एल सी के एन डी एफ बी, एन एल एफ टी/बी के साथ भी संबंध हैं। भारत की सुरक्षा पर नजर रखने वाले संबंधित अधिकारियों ने यह सूचित किया है कि एच एन एल सी की विचारधारा राष्ट्र विरोधी है। इसके अतिरिक्त ऐसी आसूचना है कि एच एन एल सी अपने कुछ नेताओं की गिरफ्तारी/आत्मसमर्पण के बावजूद पुनः एकजुट होने की स्थिति में है और वह विध्वंसक गतिविधियों को समर्थन दे सकता है। इसके अलावा ऐसी भी रिपोर्टें हैं कि शांति वार्ता के लिए मेघालय राज्य के निमंत्रण पर एच एन एल सी ने सकारात्मक प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

16. केन्द्र सरकार के गवाह ने इसके अतिरिक्त यह भी बयान दिया:

- क. कि एच एन एल सी भारत संघ से मेघालय राज्य को पृथक करने के साथ-साथ अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष में संलिप्त है तथा लोगों को डराने-धमकाने और उनसे जबरन धन-वसूली भी कर रहा है;
- ख. कि उसके अभियान अब मुख्यतः खासी हिल्स तक सीमित हैं और उसके अभी भी लगभग 52-60 काडर हैं और उनके पास ए के श्रृंखला की राइफलें, लाईट मशीनगनों और राइफलें मौजूद हैं;
- ग. कि एच एन एल सी को विधिविरुद्ध घोषित करने के लिए अधिसूचनाएं वर्ष 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 में भी जारी की गई थीं और समय समय पर गठित अधिकरणों द्वारा भी उक्त घोषणाओं को बरकरार रखा गया है किन्तु घोषणाओं के बावजूद एच एन एल सी ने अपने विधिविरुद्ध क्रियाकलापों को जारी रखा है;
- घ. कि एच एन एल सी को विधिविरुद्ध संगम घोषित किए जाने संबंधी घोषणा को जारी रखना आवश्यक समझा गया है ताकि एच एन एल सी को अलगाववादी, विद्रोही, आतंकवादी तथा हिसंक गतिविधियों में तेजी लाने से रोका जा सके तथा प्रतिबंध हटाने से एच एन एल सी के नेताओं को भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का खुले रूप से प्रचार करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा।

ड. कि प्रतिबंध के बिना पुलिस तथा सुरक्षा बलों के लिए एच एन एल सी के पकड़े गए सदस्यों को बंदी रखना तथा उन पर अभियोजन चलाना मुश्किल हो जाएगा।

17. केन्द्र सरकार के गवाह ने दिनांक 16 नवम्बर, 2004 की अधिसूचना के अनुसरण में गठित अधिकरण के दिनांक 12 मई, 2005 के आदेश तथा दिनांक 16 नवम्बर, 2006 की अधिसूचना के अनुसरण में गठित अधिकरण के दिनांक 14 मई, 2007 के आदेश एवं दिनांक 16 नवम्बर, 2008 की अधिसूचना के अनुसरण में गठित अधिकरण के दिनांक 14 मई, 2009 के आदेश को भी सिद्ध कर दिया है। प्रत्येक मामले में एच एन एल सी अनुपस्थित रहा।

18. केन्द्र सरकार के गवाह ने यह बयान दिया है कि केन्द्र सरकार के पास अधिनियम की धारा 3(1) के दायरे के भीतर यह राय बनाने के लिए, कि एच एन एल सी की गतिविधियां भारत की शांति एवं आन्तरिक सुरक्षा के लिए निरन्तर हानिकर बनी हुई हैं तथा एच एन एल सी को और दो वर्षों के लिए विधिविरुद्ध संगम घोषित करने संबंधी नई घोषणा किये जाने के लिए पर्याप्त कारण एवं सामग्री थी।

19. एस डब्ल्यू 1 के रूप में उपस्थित होने वाले मेघालय सरकार, राजनीतिक विभाग के सचिव ने:

क. यह बयान दिया है कि एच एन एल सी विभिन्न प्रेस प्रकाशनों के माध्यम से प्रत्येक राष्ट्रीय दिवस समारोहों, अर्थात् गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस समारोहों पर बन्द तथा असहयोग का आह्वान करता रहा है;

ख. प्रदर्श एस डब्ल्यू-1/1 से एस डब्ल्यू-1/6 के रूप में उन्होंने सिद्ध किया है कि "हन्नीवट्रेप राष्ट्र के भू-भाग के भीतर" भारतीय राष्ट्रीय दिवसों को मनाने के खिलाफ वर्ष 2009-2010 के दौरान भारत के स्वतंत्रता दिवस और गणतन्त्र दिवस के अवसर पर एच एन एल सी के प्रचार सचिव श्री सैकुपर नंगट्रा द्वारा इस कारण से किए गए आह्वान की प्रेस रिपोर्टें हैं कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो हन्नीवट्रेप लोगों की स्वतंत्रता का आश्वासन देने संबंधी "अवरुद्ध समझौता" (स्टैंडस्टील एग्रीमेंट) भंग हो गया; उन्होंने यह भी बयान दिया कि उक्त अह्वानों के परिणामस्वरूप ट्रेनों को रद्द करना पड़ा;

ग. 19 दिसम्बर, 2009 को भारत के गृह मंत्री के मेघालय राज्य के दौरे के विरोध में बन्द के लिए एच एन एल सी द्वारा इस कारण से किए गए आह्वान को भी

सिद्ध किया है कि भारत के केन्द्रीय गृह मंत्री उन क्षेत्रों, जो काफी समय के लिए अंग्रेजों को पट्टे पर दिए थे, में "अवैध दमन" द्वारा हन्नीवट्रेप लोगों पर शासन कर रहे हैं तथा वे भारत द्वारा किए गए हन्नीवट्रेप भूमि के बलपूर्वक कब्जे का विरोध करते हैं;

घ. एच एन एल सी के उल्फा, एन डी एफ बी, एन एस सी एन (आई एम) तथा एन एल एफ टी और अन्य विधिविरुद्ध संगठनों के साथ संबंध होने के बारे में बयान दिया है।

ङ. यह भी बयान दिया है कि विगत में एच एन एल सी को विधिविरुद्ध संगम घोषित किए जाने संबंधी घोषणा के कारण पुलिस एच एन एल सी की गतिविधियों को प्रभावकारी ढंग से कम करने में सफल रही है जिसके कारण एच एन एल सी के कम से कम 180 सदस्यों ने आत्मसमर्पण भी किया है;

च. बयान दिया है कि जब तक एच एन एल सी को विधिविरुद्ध संगम घोषित किए जाने संबंधी घोषणा को बढ़ाया नहीं जाता तब तक पुलिस एच एन एल सी की विधिविरुद्ध गतिविधियों को नियंत्रित करने में स्वयं को असहाय महसूस करेगी।

20. मेघालय राज्य के पश्चिम खासी हिल्स जिले में एच एन एल सी की गतिविधियों का साक्ष्य एस डब्ल्यू-2 के रूप में उपस्थित होने वाले जिला उपायुक्त श्री सिल्वेस्टर खरलिंगदोह, एस डब्ल्यू-3 के रूप में उपस्थित होने वाले जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. एन राजामारथंडन तथा एस डब्ल्यू-12 के रूप में उपस्थित होने वाले जिले के उप-निरीक्षक श्री अमित राजदीप ने दिया है। उन्होंने :

क. बयान दिया कि एच एन एल सी अभी भी जिले में सक्रिय है तथा अपने विधिविरुद्ध उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए धन जुटाने हेतु विधि विरुद्ध और जबरन धन वसूली की गतिविधियों में संलिप्त है;

ख. बयान दिया कि एच एन एल सी भारत की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता को हानि पहुंचा रहा है और नष्ट कर रहा है तथा जिले के मुख्यतः पोरमोदार, नोनगजरी तथा बोरसोरा क्षेत्रों में जबरन धन वसूली कर रहा है।

- ग. प्रदर्श एस डब्ल्यू-2/2 से प्रदर्श एस डब्ल्यू -2/7 के रूप में एच एन एल सी के सदस्यों/काइरों की अवैध गतिविधियों संबंधी प्रथम सूचना रिपोर्टों को सिद्ध कर दिया है;
- घ. प्रदर्श एस डब्ल्यू - 2/9 के रूप में एच एन एल सी के प्रवक्ता श्री सैंकुपार नोंगट्राव द्वारा "हन्नीवट्रैप भूमि पर हन्नीवट्रैप लोगों की स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र विद्रोह" किए जाने संबंधी ई-मेल द्वारा जारी बयान के संबंध में प्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट को सिद्ध कर दिया।
- ङ. बयान दिया कि भारत की संप्रभुता को चुनौती देने, लोगों के बीच डर का माहौल पैदा करने तथा लोगों को भारत सरकार का आदेश स्वीकार न करने के लिए उकसाने एवं भारत सरकार को चुनौती देने के लिए बन्द का आह्वान किया जाता है।
- च. बयान दिया कि एच एन एल सी भारतीय भू-भाग से पृथक होने के लिए सशस्त्र विद्रोह करने की मंशा से हथियारों की खरीद हेतु व्यापारिक समुदाय के लोगों से जबरन धन वसूली की गतिविधियों में संलिप्त है।
- छ. बयान दिया कि एच एन एल सी काइर उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो भारत के कानूनों का पालन करते हैं ताकि उन्हें भारत के कानूनों का अनुपालन करने से रोका जा सके;
- ज. अधिकरण के प्रश्न के उत्तर में बयान दिया कि उनके द्वारा सिद्ध प्रथम सूचना रिपोर्टें जांच एवं अभियोजन की संसदीय प्रक्रिया पर हैं।
- झ. श्री एलेक्स हासाह एच एन एल सी के प्रमुख सदस्य के खिलाफ अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा आठ समर्थकों, शस्त्रों, मोबाइल फोन एवं कई सिद्ध काइरों के साथ उसकी गिरफ्तारी को सिद्ध किया।
- ञ. बयान दिया कि एच एन एल सी द्वारा किए जा रहे बंद के अखंडता के कारण जिले के अधिकतर लोग गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए घरों के अन्दर ही रहते हैं तथा बार-बार राष्ट्रीय समारोहों में बाधा डाल कर एच एन एल सी अलगाववाद के अपने लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रहा है।

- ट. बयान दिया कि एच एन एल सी की एन एस सी एन (आई एम) तथा एन एल एफ टी के साथ सांठ-गांठ है तथा वे मिलकर देश की संप्रभुता, एकता तथा बाहरी एवं आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हैं।
- ठ. बयान दिया है कि एच एन एल सी ऐसी गतिविधियों में संलिप्त होकर यह संदेश प्रसारित कर रहा है कि पश्चिम खासी हिल्स जिले का प्रशासन राज्य सरकार के नियंत्रण में न होकर उनके नियंत्रण में है तथा सरकार उस क्षेत्र में विकास करने में असमर्थ है।

21. मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले में एच एन एल सी की गतिविधियों का साक्ष्य एस डब्ल्यू-4 के रूप में उपस्थित होने वाले जिला उपायुक्त श्री जोपथियु लिंगदोह, एस डब्ल्यू-5 के रूप में उपस्थित होने वाले जिला पुलिस अधीक्षक श्री खारक्रांग, श्री मातीऊस सी. संगमा उपनिरीक्षक जिला ने एस डब्ल्यू 13 के बतौर एवं श्री जैफरी डब्ल्यू सूटिंग उपनिरीक्षक जिला ने एस डब्ल्यू 14 के बतौर दिया है। उन्होंने :-

- क. उक्त जिले में एच एन एल सी की विधि-विरुद्ध, जघन्य और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के बारे में उपर्युक्त गवाहों की तर्ज पर बयान दिया;
- ख. 25 फरवरी 2011 को बयान देने की तारीख से दो हफ्ते पूर्व की घटना के बारे में बयान दिया जब एन डी एफ बी से संबंधित पांच व्यक्तियों को रि-भोई जिले में गिरफ्तार किया गया एवं पूछ-ताछ के दौरान उन्होंने बंगलादेश, में छिप रहे एच एन एल सी के श्री बॉबी मारवेन के साथ अपने संबंधों को कबूल किया;
- ग. उक्त जिले में रखे गए रिकॉर्ड के आधार पर बयान दिया कि एच एन एल सी "हन्नीवट्रेप लैण्ड" की स्वतंत्रता के लिए कार्य कर रहा है जिसका भारत के साथ कोई संबंध नहीं होगा तथा उन्होंने प्रदर्श एस डब्ल्यू-5/2 के रूप में एच एन एल सी द्वारा परिचालित एक पैम्फलेट को सिद्ध किया है जिसमें एच एन एल सी ने भारतीय उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद एवं राष्ट्रवाद से स्वतंत्रता की मांग की है तथा हन्नीवट्रेप लोगों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की है;
- घ. एचएनएलसी के एक कांडर फिकेरलांग माजा उर्फ सान का 20 मई 2009 को रिकार्ड किया गया बयान सिद्ध किया है। उक्त बयान के अनुसार एच एन एल सी के 200 कार्यकर्ता हैं और उन्हें फुट एण्ड आम ड्रिल, एके - 47, एस एल आर,

- 303 राइफल्स इत्यादि जैसे शस्त्र चलाने के प्रशिक्षण दिए गए हैं एवं चिट्गांग हिल्स ट्रैक में एच एन एल सी के एन डी एफ बी, एन एल एफ टी, के वाई के एल जैसे अन्य विधिविरुद्ध/आतंकवादी संगठनों के साथ शिविर हैं।
- ड. प्रदर्श एस डब्ल्यू 5/4 के रूप में एच एन एल सी कॉडर के दूसरे सदस्य अर्थात् श्री इमलांग बिरजू मारवेन स्मॉल, जिसने भी पूर्वी खासी हिल्स जिले में समर्पण कर दिया था, का 7 अगस्त 2009 को रिकॉर्ड किया गया बयान सिद्ध किया। उन्होंने एच एन एल सी द्वारा अपने कॉडरों को ए के 47, स्नाइपर राइफल, 303 राइफल जैसे हथियार चलाना सिखाने के लिए प्रशिक्षण शिविर चलाने तथा बंगलादेश में एच एन एल सी कॉडरों को आगे पैसा पहुंचाने के लिए नांगस्टेंग एवं माफ्यू के ग्रामीणों से धन एकत्रित करने के बारे में भी बयान दिया है।
- च. फिरौती, गम्भीर चोट पहुंचाने के लिए अपराधों के संबंध में दिसम्बर, 2009 एवं मई, 2010 में एच एन एल सी कॉडर सदस्यों के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकियां प्रदर्श एस डब्ल्यू 5/6 प्रदर्श एस डब्ल्यू 5/7 प्रदर्श एस डब्ल्यू 5/8 एवं प्रदर्श एस डब्ल्यू 5/9 सिद्ध की।
- छ. जिले में एच एन एल सी कॉडरों द्वारा किए जाने वाले बंद के आह्वानों को सिद्ध किया।
- ज. एच एन एल सी द्वारा पूर्वोत्तर भारत के यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा), नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम (एन एस सी एन), डिमॉक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैन्ड (एन डी एफ बी) तथा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एन एल एफ टी) जैसे अन्य राष्ट्र विरोधी उग्रवादी संगठनों के साथ अभी भी अच्छे संबंध बनाए रखने की आसूचना इनपुट्स के आधार पर जानकारी होने के बारे में बयान दिया।
- झ. बयान दिया कि एच एन एल सी का मुख्य उद्देश्य भारत संघ से स्वतंत्र एक संप्रभु 'खासी हिल्स राष्ट्र' गठित करना है तथा उसके सदस्य उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए धन एकत्रित करने हेतु अपराध कर रहे हैं तथा भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

- ज. बयान दिया कि 25 फरवरी, 2011 को बयान देने की तारीख से कुछ दिन पूर्व एच एन एल सी ने जिले के एक नागरिक को 50,00,000 रु. की मांग के लिए नोट भेजा था।
- ट. अधिकरण के प्रश्न पर यह सूचित किया कि दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्टों के आधार पर कार्यवाही की जा रही है तथा एक मामले में चार्जशीट दर्ज कर दी गई है तथा अन्य मामलों की जांच चल रही है।

22. मेघालय राज्य के जैंतिया हिल्स जिले में एच एन एल सी की गतिविधियों का साक्ष्य श्री टी. इकार, जिला उपायुक्त ने एस डब्ल्यू-6 के रूप में, श्री ओ. पासी जिला पुलिस अधीक्षक ने एस डब्ल्यू-7 के रूप में तथा श्री क्यू.ई. पाला, जिला उप निरीक्षक ने एस डब्ल्यू-15 के रूप में दिया है। उन्होंने;

- क. एच एन एल सी के अभी भी सक्रिय होने का इसी प्रकार का बयान दिया है;
- ख. एच एन एल सी तथा इसमें काडरों द्वारा किए गए अपराधों के बारे में 5 अगस्त 2010 की प्राथमिकी को प्रदर्श एस डब्ल्यू-6/2 के रूप में प्रमाणित किया;
- ग. अधिकरण के सवाल के प्रत्युत्तर में बयान दिया कि भारत में राष्ट्रीय महत्व के दिवसों को मनाने से लोगों को रोकने के लिए एच एन एल सी बंद का आह्वान करता है और ये बंद आंशिक रूप से सफल भी रहते हैं;
- घ. एच एन एल सी के दो सदस्यों की गिरफ्तारी संबंधी बयान दिया, जो वर्ष 2011 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर किए गए बंद के आह्वान को बलपूर्वक लागू कराने की कोशिश कर रहे थे;
- ड. यह बयान दिया कि एच एन एल सी का मुख्य उद्देश्य भारत से अलग होना था;
- च. स्वतंत्रता दिवस समारोहों में गड़बड़ी पैदा करने के उद्देश्य से इस्तेमाल किए जाने वाले शस्त्रों की भारी मात्रा में बरामदगी के बारे में बयान दिया और इस संबंध में जब्ती जापान एवं दोषी व्यक्तियों के रिकार्ड किए बयान की पुष्टि की।

23. मेघालय राज्य के री-भोई जिले में एच एन एल सी की गतिविधियों का साक्ष्य, श्री मावशॉन खरमुजई, जिला उपायुक्त द्वारा एस डब्ल्यू-8 के रूप में, श्री स्मिति सी.ए. लिगंगा, जिले के

पुलिस अधीक्षक द्वारा एस डब्ल्यू-9 के रूप में, श्री एम.कोच, जिले के पुलिस उप निरीक्षक द्वारा एस डब्ल्यू-10 के रूप में तथा श्री ई.डी. मन्नार, जिले के पुलिस उप-निरीक्षक द्वारा एस डब्ल्यू-11 के रूप में दिया गया है। उन्होंने

- क. श्री इमैरसन मैटिंग उर्फ फ्रेडी उर्फ बाह हेप की दिनांक 04 सितम्बर, 2010 को गिरफ्तारी तथा पूछताछ के दौरान हथियारों में एच एन एल सी काडर के प्रशिक्षण शिविरों तथा भारत में अपराध करने के बाद बंगला देश में उनके छिपने और दिसम्बर, 2010 के दौरान/जनवरी, 2011 के प्रथम सप्ताह में बंगलादेश में हुई एच एन एल सी काडरों की बैठक एवं एन डी एफ बी के साथ एच एल सी के संयुक्त अभियानों के बारे में दिए गए बयान प्रमाणित किए।
- ख. दिनांक 10 फरवरी, 2011 की प्राथमिकी (एफ आई आर) को प्रदर्श एस डब्ल्यू-10/2 के रूप में प्रमाणित किया तथा श्री लशित बोरो द्वारा दिए गए बयान को प्रदर्श एस डब्ल्यू-10/6 के रूप में प्रमाणित किया। उक्त श्री लशित बोरो ने एच एन एल सी, जिसका वह एक सदस्य था, के राष्ट्रविरोधी कार्यकलापों के बारे में उसी प्रकार का बयान दिया है।
- ग. दिनांक 15 फरवरी, 2011 की प्राथमिकी (एफ आई आर) को प्रदर्श एस डब्ल्यू-11/13 के रूप में प्रमाणित किया तथा एच एन एल सी के गिरफ्तार किए गए काडरों के बयानों और बरामद वाचन सामग्री को प्रमाणित किया जो समान रूप से उन राष्ट्र विरोधी कार्य कलापों को सिद्ध करते हैं जिनमें एच एन एल सी के सदस्य संलिप्त हैं।

24. उपर्युक्त सामग्री एवं साक्ष्य के आधार पर यह न्याय निर्णय किया जाना है कि क्या भारत सरकार द्वारा बनाया गया मत औचित्यपूर्ण है या नहीं तथा क्या एच एन एल सी को एक विधि विरुद्ध संगम घोषित करने संबंधी अधिसूचना विधिक रूप में तर्क संगत है और क्या इस घोषणा की पुष्टि की जाए या इसे निरस्त किया जाए।

25. इन कार्यवाहियों की प्रकृति तथा इनमें अपनाई जाने वाली कार्यविधि के बारे में, एच एन एल सी के संबंध में अधिनियम के अंतर्गत पूर्व अधिसूचना के अनुसरण में, पूर्व में गठित अधिकरण की दिनांक 14 मई 2007 की रिपोर्ट के पैरा 85 से 88 में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई

है और इसलिए कानूनी स्थिति को दोहराने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है। यह निर्णय लिया गया था कि ये कार्यवाहियां विचारण प्रकृति की नहीं हैं तथा अधिकरण मोटे तौर पर केवल इस बारे में पूछताछ करेगा कि क्या संगम को विधिविरुद्ध घोषित किया जाना है। यह देखने के लिए कि अधिकरण की कार्यविधि निष्पक्ष एवं तर्कपूर्ण है, *जमात-ए-इस्लामी हिन्द बनाम भारत संघ* (1995) 1 एस सी सी 428 का सहारा लिया गया था, क्योंकि इसके निर्णय में संगम के मौलिक अधिकार के सीमित किए जाने की संभावना है, हालांकि यह कुछ सीमित अवधि के लिए होगा। यह निर्णीत हुआ कि अपनायी जाने वाली न्याय निर्णयन प्रक्रिया, कोई मुकदमा नहीं होगा तथा इसकी कार्यविधि, किसी पूछताछ जैसी होगी जिसका उद्देश्य अंतिम निर्णय तक पहुँचने के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित करना होगा। कार्यविधि के रूप में, यह व्यवस्था दी गई कि जहाँ तक संभव हो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के उपबंधों का अनुपालन किया जाए, तथापि, कार्यवाहियों की प्रकृति को देखते हुए तथा कार्यवाही के दौरान अधिकरण के समक्ष संभावित रूप से उजागर होने वाली संवेदनशील प्रकृति की सामग्री की संभावना के मद्देनजर, अधिकरण प्रमाण संबंधी नियमों से आबद्ध नहीं होगा और उसे उनका अनुसरण अभिप्राय के आधार पर करना होगा।

26. उक्त अधिनियम की धारा 2 (ण) के अंतर्गत विधिविरुद्ध कार्यकलापों की परिभाषा में संशोधन किया गया था ताकि अभिव्यक्ति "अथवा" को जोड़ते हुए (i), (ii) तथा (iii) को शामिल किया जा सके। इस परिभाषा खण्ड के संशोधन से 'विधिविरुद्ध कार्यकलाप' अभिव्यक्ति का दायरा व्यापक रूप से बदल गया है। संशोधन-पूर्व परिभाषा खण्ड में (i) तथा (ii) दोनों अंशों को संतुष्ट करना आवश्यक है जबकि संशोधित खण्ड के अंतर्गत, धारा 2 की उपधारा (ण) के अंतर्गत उल्लिखित तीन खण्डों में से किसी के भी संतुष्ट होने पर यह एक 'विधिविरुद्ध कार्यकलाप' होगा। "कोई व्यक्ति अथवा संगठन" "जो भारत के खिलाफ राजद्रोह करता है अथवा राजद्रोह का इरादा करता है" वह "व्यक्ति अथवा" "संगठन" विधिविरुद्ध कार्यकलाप में शामिल माना जाएगा। "राजद्रोह" की व्याख्या में देशद्रोह एवं शत्रुता के सभी भावों को शामिल किया गया है। यह राजद्रोह की किस्म है और लोग सरकार से असंतुष्ट रहते हैं। सामान्य शब्दों में, यह विधि विरुद्ध तरीकों से प्रशासन को चुनौती देने का ढंग है। इस अभिव्यक्ति को व्यापक अर्थ देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने "सप्ताह" एक बंगाली द्विसाप्ताहिक समाचार पत्र तथा बिनय चट्टोपाध्याय, ए. आई आर 1950 कलकत्ता 445 के मामले में निम्नवत निर्णय दिया:

“ ‘राजद्रोह’ शब्द का अर्थ राजनीतिक अलगाव अथवा असंतोष है, जिसका तात्पर्य, विद्यमान सरकार के प्रति एक अनिष्टा का भाव है, जो अवज्ञा की स्थिति की ओर अग्रसर न होकर सरकार का प्रतिरोध करने एवं इसे समाप्त करने की ओर उन्मुख होता है” ।

27. धारा-2 (त) में ‘विधिविरुद्ध संगम’ की व्याख्या किसी ऐसे संगठन के रूप में की गई है “जिसके पास अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई विधिविरुद्ध कार्यकलाप हो, अथवा जो लोगों को विधिविरुद्ध कार्य कलाप करने के लिए प्रोत्साहित करता हो अथवा सहायता प्रदान करता हो, अथवा जिसके सदस्य ऐसे कार्यकलाप को अंजाम देते हों।” विधानमंडल, इस भाष्यकारी उप-धारा को एक व्यापक अर्थ एवं निर्वचन प्रस्तुत करना चाहता था और यही वास्तविक कारण है कि उक्त धारा में “बढ़ावा देता है” (एंकरिजेज), “सहायता प्रदान करता है” (एड्स) जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहां तक कि यदि कोई संगठन अपने उद्देश्य के लिए किसी ऐसे कार्यकलाप का सहारा लेता है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 153-क अथवा 153-ख के अंतर्गत दण्डनीय है, अथवा जिसके सदस्य ऐसे कार्यकलापों को अंजाम देते हैं, तो वह एक ‘विधिविरुद्ध संगम’ होगा। अधिकरण के पास इस बात का कोई कारण नहीं है कि वह इसे एक सीमित व्याख्या/अर्थ दे। किसी भी दशा में, एच एन एल सी की उल्लिखित गतिविधियां राष्ट्र की संप्रभुता के लिए खुली चुनौती हैं उनकी विधिविरुद्ध गतिविधियां, जिनमें जबरन धन वसूली, अपहरण, हत्या और सुरक्षा बलों पर हमले तथा खनिज सम्पदा के दोहन में हस्तक्षेप के द्वारा लोगों के मन में भय उत्पन्न करना शामिल है, विधिविरुद्ध और अवैध तरीकों द्वारा राज्य के प्रशासन में बाधा डालने में इन संगमों के हमले के स्पष्ट संकेत हैं। एच एन एल सी को अभी भी अर्थात् वर्ष 2008 की पिछली अधिसूचना के बाद भारत की संप्रभुता और अखण्डता को विघटित करने, शस्त्र जुटाने, भारत संघ की सीमा का उल्लंघन करने, भारतीय भूभाग की सीमाओं के भीतर और बाहर अन्य प्रतिबंधित संगठनों और विधिविरुद्ध संगमों के साथ अपने सम्पर्क बनाए रखने में लिप्त पाया गया है।

28. भारत संघ और अन्य बनाम सुकुमार सेन गुप्ता और अन्य ए आई आर 1990 एस सी 1692 के मामले में संप्रभुता को न्यायालय द्वारा अधिकार की गुणवत्ता, अधिकारों का एक पुंज बताया गया है और कि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आधुनिक विकसित समाजों की जटिलताओं के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का सौहार्दपूर्ण और शान्तिपूर्ण समाधान किए जाने की आवश्यकता है और संप्रभुता तथा स्वतंत्रता

की अभिव्यक्ति को घटनाक्रम के दृष्टिगत आशोधित किया जाना था। इसके अधिकारों का एक पुंज होने के नाते अपने समाज के सदस्यों की सुरक्षा करना राष्ट्र के दायित्व को सर्वोपरि रखा गया है। इस प्रकार निर्धारित कानून के सामान्य सिद्धांतों के लिए विधिविरुद्ध संगठनों और उस दिशा में विधिविरुद्ध गतिविधियों की व्याख्या करना जरूरी है। यदि इस प्रकार के विधिविरुद्ध संगम के सदस्य सड़क पर आम आदमी को आतंकित करते हैं और पूर्वोक्त उद्देश्यों के साथ राष्ट्र के विभिन्न साधनों द्वारा सामान्य प्रशासन के लिए कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा करते हैं, तो उनका यह कार्य न केवल इरादतन किया गया होगा बल्कि वास्तव में भारत की संप्रभुता और भूभागीय अखण्डता को विघटित करने वाला होगा।

29. संप्रभुता की अवधारणा के महत्व को स्पष्ट करते हुए उच्चतम न्यायालय ने सिन्थेटिक एंड केमिकल्स लिमिटेड तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य (1990) 1 एस सी सी 109 में यह निर्णय दिया कि "यह संप्रभुता की प्रक्रिया है जिसमें राज्य को अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए संविधान की सीमाओं के अध्यधीन कोई कानून अधिनियमित करने का पर्याप्त प्राधिकार प्रदान किया गया है। भारत राष्ट्र को, केन्द्र और राज्यों के बीच संप्रभुता प्राप्त है। संप्रभुता, प्रत्येक संप्रभुता सम्पन्न राष्ट्र में ऐसे सभी कार्य करने के लिए परिपूर्ण और अंतर्निहित होती है जिनसे लोगों के स्वास्थ्य, शान्ति, मनोबल, शिक्षा और सुव्यवस्था में सहायता मिलती है। तथापि, प्रभुसत्ता की यह शक्ति संवैधानिक सीमाओं के अध्यधीन है।"

30. उल्लिखित विधि के सिद्धान्तों से यह पता चलता है कि "संप्रभुता" अभिव्यक्ति का ऐसा अर्थ लगाना होगा जिसे आम बोलचाल में समझा जा सके और यह निश्चित रूप से व्यापक आयामों वाली अभिव्यक्ति है। प्रभुसत्ता की शक्ति का उद्देश्य अंततः राष्ट्र की जनता के कल्याण के लिए है इसलिए इसके इस प्रकार के कार्यों का बिना किसी बाधा के निर्वहन करने में किसी संगम अथवा व्यक्तियों के किसी समूह द्वारा विधिविरुद्ध बाधाएं उत्पन्न करना और धमकी देना लोकतान्त्रिक प्रणाली के आधारभूत सिद्धांतों का उल्लंघन होगा।

31. मेघालय राज्य की ओर से सभी गवाहों द्वारा दिए गए बयानों से यह पता चलता है कि एच एन एल सी पूर्वी और पश्चिमी खासी हिल्स जिलों, जैतिया हिल्स जिले और रि- भोई जिले में सक्रिय बना हुआ है और अपनी कारवाइयों को अंजाम दे रहा है। मेघालय राज्य की ओर से गवाहों के अनुसार यह एन एस सी एन, उल्फा, एन डी एफ बी, के एन वी और एन एल एफ टी

आदि जैसे प्रतिबंधित संगठनों के साथ सक्रिय सम्पर्क बनाए हुए हैं। ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जिनमें एच एन एल सी के काडरों को गिरफ्तार किया गया अथवा उन्होंने आत्म समर्पण किया जिसके परिणामस्वरूप उनसे हथियार बरामद किए गए। साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि एच एन एल सी ने वर्ष 2009 और 2010 में लोगों को धमकी दी तथा उन्हें गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय समारोहों में भाग लेने से रोका। इसके अतिरिक्त गवाहों ने यह साक्ष्य दिया कि एच एन एल सी हन्नीवट्रेप लोगों के लिए भारत के भूभाग से अलग एक पृथक राष्ट्र चाहता है। इन गवाहों, जिनमें चार जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक तथा एच एन एल सी की विधिविरुद्ध गतिविधियों के संबंध में दर्ज एफ आई आर के जांचकर्ता अधिकारी शामिल हैं, के अनुसार एच एन एल सी का शीर्ष नेतृत्व भारत की सीमा से बाहर बंगलादेश में अपना ठिकाना बनाए हुए है। एच एन एल सी प्रशिक्षण तथा संसाधन निर्माण आदि के लिए विधिविरुद्ध घोषित अन्य संगमों की भी सहायता लेता है।

32. अकाट्य साक्ष्य के विश्लेषण से यह पता चलता है कि एच एन एल सी एक ऐसा संगठन है जो हन्नीवट्रेप लोगों के लिए भारत से अलग एक पृथक अथवा स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस उद्देश्य को वह हिंसा के कृत्यों के माध्यम से हासिल करना चाहता है। हिंसा के इन कृत्यों में पुलिस कार्मिकों पर हमले, परिष्कृत और अवैध हथियारों का प्रयोग, राष्ट्रीय दिवस समारोहों में भाग न लेने के लिए बार-बार लोगों से कहना शामिल है। इस साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि एच एन एल सी ने इस अधिनियम की अनुसूची में अधिनियम की धारा 2(त) (ड) और धारा 35 के अंतर्गत विधि विरुद्ध अथवा आतंकवादी संगठन घोषित किए गए अन्य संगठनों के साथ संपर्क और संबंध कायम किए हुए हैं। इसके नेता बंगलादेश में हैं, जहां उन्होंने काडरों को प्रशिक्षित करने के लिए शिविर चलाए हुए हैं और जहां वे अपहरण, जबरन धन-वसूली तथा हिंसा के अन्य कृत्यों को अंजाम देने के बाद भाग जाते हैं।

33. चार जिलों के संबंध में दिए गए साक्ष्य में एक समान बात प्रतीत होती है- उनका उद्देश्य लोगों को डराना-धमकाना, सामान्य कार्यकरण में बाधा डालना और जबरन धन वसूलने और अपहरण के माध्यम से आर्थिक व्यवस्था को ध्वस्त करना है। एच एन एल सी द्वारा लोगों को राष्ट्रीय समारोहों में भाग लेने से रोकने की बार-बार धमकियाँ और उन्हें डराने धमकाने की घटनाओं में देश की खनिज सम्पदा अर्थात् यूरेनियम को हन्नीवट्रेप लोगों से संबंधित होने की

घोषणा करना, पृथक राष्ट्र के उद्देश्य को सशस्त्र संघर्ष और हिंसा के माध्यम से हासिल करने के लिए हिंसा के मार्ग पर चलने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना शामिल है। इससे यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि इसकी गतिविधियों का कोई विधिसम्मत उद्देश्य नहीं है बल्कि इनका उद्देश्य भारत की संप्रभुता और भू-भागीय अखण्डता को कम करना तथा नष्ट करना है।

34. प्रस्तुत साक्ष्य और रिकार्ड में प्रस्तुत की गई सामग्री के आधार पर मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि एच एन एल सी की विधिविरुद्ध गतिविधियाँ जारी हैं जो अहितकर हैं तथा भारत की भू-भागीय अखण्डता को विघटित करने वाली हैं। मैं इस बात से भी संतुष्ट हूँ कि एच एन एल सी के अनेक काइर सदस्यों की गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण के बावजूद यह अभी भी भारत की भूभागीय अखण्डता के लिए अहितकर, विघटनकारी गतिविधियों में सक्रिय और लिप्त है।

35. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए और रिकार्ड में मौजूद सभी सामग्रियों पर विचार करने के पश्चात् इस अधिकरण का मत है कि धारा 3(1) के अंतर्गत उक्त अधिसूचना की पुष्टि करने के लिए भारत संघ और मेघालय राज्य द्वारा पर्याप्त साक्ष्य दिए गए हैं।

36. अतः मेरा यह दृढ़ मत है कि एच एन एल सी को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने का पर्याप्त कारण मौजूद है। तदनुसार अधिनियम की धारा 4(3) के अनुसार यह अधिकरण अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसरण में 'हन्नीवट्रेप नेशनल लिब्रेशन काउंसिल' को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने संबंधी दिनांक 16 नवम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या 2792 (अ) की एतद्वारा पुष्टि करती है।

37. अधिकरण की कार्यवाहियों का समस्त रिकार्ड, पुनः सील किए गए सीलबंद लिफाफे सहित केन्द्र सरकार को इस आदेश के साथ प्रस्तुत किया जाए।

न्यायमूर्ति राजीव सहाय एन्डलॉ
विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण

दिनांक 13 मई, 2011

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st June, 2011

S. O. 1268(E).—In terms of Section 4(4) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the order of the Tribunal presided over by Hon'ble Mr. Justice Rajiv Sahai Endlaw, Judge Delhi High Court, to whom a reference was made under Section 4(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the Hynniewtrep National Liberation Council (HNLC) organization of Meghalaya as unlawful is published for general information :

[F. No. 11011/56/2010-NE. III]

SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.

BEFORE HON'BLE MR. JUSTICE RAJIV SAHAI ENDLAW JUDGE, DELHI HIGH COURT, NEW DELHI
THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL

IN RE:

NOTIFICATION NO. S.O. 2792 (E) DATED 16TH NOVEMBER 2010 ISSUED BY THE GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF HOME AFFAIRS, NEW DELHI IN EXERCISE OF POWERS UNDER SECTION 3(1) OF THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) ACT, 1967 DECLARING HYNIEWTREP NATIONAL LIBERATION COUNCIL OF MEGHALAYA AS AN UNLAWFUL ASSOCIATION.

ORDER**13-05-2011**

1. By a Notification No. S.O. 2792(E) dated 16th November, 2010 issued in exercise of powers under Section 3(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (hereinafter called the Act), the Central Government declared that it was of the opinion that, the Hynniewtrep National Liberation Council (hereinafter called HNLC) of Meghalaya along with all its factions, wings and front organizations are an unlawful association. The grounds, within the meaning of Section 3(2) of the Act for issuance of the Notification, as set out in the Notification are as under:

A. That HNLC:

- (i) Has been openly declaring as its objective the secession of the State of Meghalaya from the Indian Union;
- (ii) Has been employing and engaging in armed means to achieve their objective;
- (iii) Has been indulging in acts of intimidation and extortion for collection of funds for their organization;
- (iv) Has been maintaining links with other insurgent groups of the North Eastern Region for carrying out extortion and intimidation;
- (v) Has been maintaining camps in some neighbouring countries for the purpose of sanctuary or training; and
- (vi) Is detrimental to the sovereignty and integrity of India.

B. That if activities of HNLC are not immediately curbed and controlled, the said HNLC would regroup and re-arm itself, expand its cadres, procure sophisticated weapons, cause heavy loss of lives of civilians and Security Forces, and accelerate its anti-national activities;

C. That it is necessary to declare the HNLC alongwith all its factions, wings and front organizations as unlawful associations with immediate effect.

2. By another Notification No. S.O. 2934 (E) dated 13th December, 2010 in terms of Section 5(1) of the Act, the Tribunal consisting of the undersigned was constituted for the purposes of adjudicating, whether or not there is sufficient cause for declaring HNLC as an Unlawful Association.

3. The reference under Section 4(1) of the Act of the Notification under Section 3(1) (supra) was made on 21 1st December, 2010 vide letter bearing No. 11011/56/2010-NE. III dated 21st December, 2010 of Mr. R. R. Jha, Joint Secretary (NE. II) Ministry of Home Affairs, Government of India, sent to the Tribunal along with two Notifications aforesaid and a brief

resume regarding the aim/objectives and violent activities of HNLC. The aforesaid documents were directed by the Registrar of the Tribunal to be placed before the undersigned on 23rd December, 2010 when Mr. A.S. Chandhiok, learned Additional Solicitor General on behalf of the Union of India and Mr. Ranjan Mukherjee, Advocate on behalf of the State of Meghalaya also appeared.

4. On 23rd December, 2010, notice under Section 4(2) of the Act was ordered to be issued to HNLC to show cause, within 30 days, as to why it be not declared unlawful. The notice was directed to be served on HNLC, (i) by affixation of a copy of the Notification on some conspicuous part of the office(s), if any of HNLC; (ii) by serving a copy of the Notification, wherever possible, on the principal Office bearers of HNLC; (iii) by proclaiming by beat of drums or by means of loudspeakers, the contents of the notification in the area in which the activities of HNLC are ordinarily carried on; (iv) by making an announcement over the radio from the local or nearest broadcasting station of the All India Radio (v) by pasting the notification on the Notice Board of the Office of the Deputy Commissioners at the headquarters of each of the seven districts in the State of Meghalaya; and, (vi) by publication in a National Newspaper in English and in one vernacular newspaper of the respective States in which the activities of the HNLC are ordinarily carried on. The Central Government was directed to make necessary and adequate arrangements for service of the notice. The notice as aforesaid, under signature of Registrar of Tribunal was issued for 28th January, 2011 at 4.00 p.m.

5. Shri Shambhu Singh, Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs filed an affidavit dated 27th January, 2011 certifying the factum of service of the notice aforesaid issued by various modes as directed. According to the affidavit, the Notification dated 16th November, 2010 (supra) was forwarded to the Chief Secretary, Government of Meghalaya for taking further necessary action in terms of Section 3(4) of the Act; that the Notification was republished in the Official Gazette of State of Meghalaya and subsequently also published in some of the local newspapers; the notice was also served, by publication in the local newspapers on 8th January, 2011, by broadcasting on All India Radio, Shillong, by telecast through the Doordarshan Kendra, Shillong and also by affixing/hanging on the Notice Board of the Office of the Deputy Commissioners of East Khasi Hills District, Ri Bhoi District, Nongpoh, West Khasi Hills District and East Garo Hills, Williamnagar of the State.

6. On 28th January, 2011, on the basis of the material produced of service of notice as aforesaid, I was satisfied that notice had been duly served. However, none appeared for HNLC. The learned ASG for the Union of India and the counsel for the State of Meghalaya sought time to file evidence by way of affidavits and which was allowed and the matter was adjourned to 17th February, 2011 at Delhi for further consideration. On suggestion of the counsel for the State of Meghalaya that to allow local participation if any, the witnesses be examined at Shillong, the examination of witnesses was scheduled on 25th and 26th February, 2011 at Hotel Pine Wood at Shillong at 10.30 a.m. in the morning. The State counsel was directed to publish the time and place of hearing by all modes as directed earlier, to enable local participation, if any.

7. On 17th February, 2011 the counsel for the State produced an affidavit of Sh. B. Dhar, Secretary to Government of Meghalaya, Political Department, Shillong, Meghalaya regarding compliance of the directions as to publication of the time and place of hearing. An affidavit on merits was also produced and on request the time for producing the remaining affidavits was extended till 25th February, 2011. The counsel for the State also informed that owing to certain exigencies Hotel Pine Wood, Shillong was not available for hearing on 25th and 26th February, 2011. Accordingly, the venue of hearing was changed to Hotel Polo Tower, Shillong and direction issued for notifying the change of venue of hearing in the manner as earlier ordered.

8. The next hearing of the Tribunal was held at Shillong on 25th February, 2011 as ordered. The counsel for the State Government informed that the change of venue of hearing had been published as directed and sought time to produce affidavit of compliance on the next date i.e. 26th February, 2011. None appeared for HNLC on 25th and 26th February, 2011 also and being satisfied of notice having been issued to HNLC, need was not felt to await further and the counsel for the State directed to produce his witnesses. The counsel informed that the State intended to produce nine witnesses.

9. During the hearing on 25th February, 2011 five witnesses of the State were examined and the matter was adjourned to 26th February, 2011 for examination of other witnesses.

10. On 26th February, 2011 the counsel for the State produced an affidavit of compliance of the order dated 17th February, 2011 regarding service of notice of the change of venue; the remaining four witnesses of the State were examined and the State of Meghalaya closed its evidence. The counsel for the Central Government stated that only one witness was to be examined and permission was granted to examine the said witness at Delhi and the proceedings at Shillong were accordingly closed.

11. The Central Government on 4th April, 2011 examined Mr. J. P. N. Singh Director, Ministry of Corporate Affairs, Government of India as its witness and closed its evidence. However, the State of Meghalaya sought and was allowed to examine additional witnesses.

12. On 25th April, 2011, the State of Meghalaya examined six additional witnesses and again closed the evidence. Arguments were heard from the learned ASG and the State of Meghalaya on 29th April, 2011, 2nd May, 2011 and 4th May, 2011 and 10th May, 2011. HNLC remained ex parte throughout the proceedings.

13. According to the brief resume forwarded along with the reference :

- A. The HNLC was formed in 1992 with the aim of liberation of Hynniewtrep people (Khasi and Jaintia tribes) from the authoritarian rule of the Indian Government, protect the Khasis and other Meghalaya tribes from exploitation, retain the indigenous culture and to eradicate social evils. It also vows to fight against any attempt to divide Khasi society.
- B. HNLC continues to indulge in intimidation and extortion. On 27th January, 2010, Meghalaya Police arrested Alex Hahshah a hardcore HNLC cadre along with 8 other HNLC cadres from West Khasi Hills district of Meghalaya. The police seized arms and ammunition from the arrested cadres of the outfit. On April 6, 2010 HNLC served a demand of Rs. 30 lakhs to Kim Marbaniang, Proprietor of Kun Hyundai Shillong. On 27th May, 2010, Border Security Force (BSF) apprehended Pariston Pakyntein, Self Styled Sergeant Major, HNLC. During the interrogation Pariston Pakyntein admitted he along with his associates had kidnapped one Phershal Kongwang on 16th December, 2007 and took him to Bangladesh where he was killed. He also admitted that on 22nd February, 2009 he along with his associates had gone to Mawriang village to settle scores with Shri Trop Suting who refused to pay extortion money demanded by the outfit on 31-1-2009. Shri Kular Suting the son of Shri Trop Suting was shot by the outfit critically injuring him.
- C. HNLC has been opposing uranium mining in Meghalaya. On January 10, 2008, the outfit declared that it would not spare any organization or individual supporting uranium mining, as the ore was the 'rightful property' of the Hynniewtrep people and not of India. The outfit has also been opposing Independence Day celebrations. The outfit called 36 hours bandh w.e.f. 6 p.m. on August 14, 2010 in Khasi Hills, Jaintia Hills of Ri Bhoi district in protest against celebration of Independence Day 2010. The outfit had also called a 24 hrs bandh on 14th August, 2009 to protest against Independence Day celebrations.
- D. HNLC continues to maintain links with the National Democratic Front of Bodoland (NDFB), National Liberation Front of Tripura (Biswamohan Debbarma) and National Socialist Council of Nagaland (Isac - Muviah) [NSCN (I/M)]. According to available information, the outfit has camps/shelters in Bangladesh, and its top leaders, Bobby Marwein, Self Styled Commander in Chief and Cheristerfiled Thangkhiew, Self Styled General Secretary, continue to operate from Bangladesh.
- E. HNLC is primarily operating in Khasi Hills of Meghalaya. The HNLC is estimated to have about 50 to 60 cadres. The outfit at present is estimated to possess about 20 weapons including AK series rifles, Light Machine Guns and Rifles.
- F. In the background of the activities of HNLC as given in preceding paragraphs, HNLC has been declared 'unlawful association' for a period of two years beyond 15th November, 2010 on the following grounds :
 - (i) Openly declared objective of HNLC for secession of areas in the State of Meghalaya largely inhabited by Khasi and Jaintia tribals from India;
 - (ii) Continued intimidation and extortion of civilian population by HNLC for collection of funds for their organization;
 - (iii) Maintaining links with other insurgent groups of the North Eastern region for carrying out acts of extortion and intimidation;
 - (iv) Maintenance of camps in Bangladesh for the purpose of sanctuary and training of their cadres.
- G. The activities of the HNLC are continuing, and it was felt that if there were any delay in extension of the notification, this organization may take undue advantage of the situation and mobilize its cadres for escalating secessionist, subversive and violent activities. It may also provide an opportunity to the leadership of this organization to openly propagate anti-national activities in collusion with foreign elements inimical to India's security concerns. The Police and the Security Forces in such an eventuality will also find it difficult to detain and prosecute the members or cadres of the outfit. It was, therefore, considered necessary to extend the notification banning HNLC for a further period of two years from the date of its publication in the Official Gazette.
- H. Government of Meghalaya, Ministry of Defence, Intelligence Bureau, Cabinet Secretariat (Research and Analysis Wing), Central Reserve Police Force and Border Security Force had recommended the continuance of declaration of the HNLC as an 'unlawful association'.

14. The sole witness of the Central Government has deposed:

- A. that HNLC was formed in 1992 with the aim of liberation of Hynniewtrep people (Khasi and Jaintia tribes) from the authoritarian rule of the Indian Government;
- B. that its present office-bearers are Sh. Bobby Marwein (Self Styled Commander in Chief) and Sh. Cheristerfiled Thangkhiew (Self Styled General Secretary);
- C. that HNLC works towards the objective of destruction of nationalism and secession of State of Meghalaya from Indian Union;
- D. that for achieving the said objective, HNLC has been engaging in armed struggle, intimidating civilians and collecting funds from them;
- E. that HNLC continues to maintain links with other unlawful associations namely National Democratic Front of Bodoland (NDFB) and the National Liberation Front of Tripura (NLFT) and also with National Socialist Council of Nagaland (Isak - Muviah) [NSCN (I/M)], a militant outfit of Nagaland;
- F. that top leaders of HNLC to avoid arrest maintained camps/shelters in Bangladesh;
- G. that HNLC has been opposing Uranium mining in Meghalaya claiming it to be property of Hynniewtrep people and not of India and threatening those involved in the same;
- H. that HNLC has been opposing the national day (Republic Day & Independence Day) celebrations of India;
- I. that the Central Government had received inputs and information from intelligence and State agencies and State Government of Meghalaya of the unlawful activities and activists of HNLC;
- J. that these reports/inputs are privileged and confidential in nature and cannot be made available to HNLC or to any third party as the Government considered it against the public interest to disclose these reports;
- K. that the activities are clandestine in nature and thus the source of inputs of the outfit's unlawful activities as natural corollary are required to be kept confidential.

15. The said witness, during his deposition, handed over a sealed envelope containing the information on the basis whereof *inter alia* the Notification dated 16th November, 2010 was issued. The said sealed envelope has been opened and the contents thereof perused. It is found to contain reports from various officials, required and expected in the course of performance of their official duty to keep track of the activities of unlawful association within the meaning of the Act aforesaid and to otherwise safeguard the integrity and sovereignty of India, of HNLC rendering active support to NSCN (I/M) and of aiming to liberate the Hynniewtrep i.e. Khasi and Jaintia population of the State from the authoritarian rule of the Indian Government and of continuing to terrorize other citizens of the State including for the purposes of collecting funds to achieve their objective. The said documents also disclose that HNLC has been threatening that it would not allow Uranium mining, claiming the same to be the property of Hynniewtrep people and not of India. There are reports of links of HNLC with NDFB, NLFT/B also. The officers concerned with keeping a watch on the security of India have reported that HNLC has an anti-national ideology. There are yet further intelligence inputs of HNLC being still in a position to regroup and support subversive activities despite arrest/surrender of some of its leaders. There are yet further reports of HNLC having not responded positively to the offer of the Government of Meghalaya for peace talks.

16. The witness of the Central Government has further deposed :

- A. that HNLC, to achieve its objectives *inter alia* of secession of the State of Meghalaya from the Indian Union has been engaging in armed struggle and have been intimidating civilian and extorting funds from them;
- B. that its operations are now primarily confined to Khasi Hills and it still has about 52-60 cadres and possess AK series rifles, Light Machine Guns and Rifles;
- C. that Notifications declaring HNLC as unlawful were issued in the year 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 also and the Tribunals constituted from time to time have been upholding the said declarations but despite the declarations, HNLC has continued its unlawful activities;
- D. that the continuation of the declaration of HNLC as an unlawful association is felt necessary to prevent HNLC from escalating secessionists, subversive, terrorist and violent activities and lifting of the ban would provide opportunity to the leadership of HNLC to openly propagate anti-national activities in collusion with foreign powers inimical to India's security concern;
- E. that the Police and Security Forces without the ban find it difficult to detain and prosecute the members of HNLC apprehended by them.

17. The witness of the Central Government has also proved the order dated 12th May, 2005 of the Tribunal constituted pursuant to the Notification dated 16th November, 2004; the order dated 14th May, 2007 of the Tribunal constituted pursuant to the Notification dated 16th November, 2006; and the order dated 14th May, 2009 of the Tribunal constituted pursuant to the Notification dated 16th November, 2008. HNLC remained ex parte in each case.

18. The witness of the Central Government has thus deposed that there was sufficient reason and material for the Central Government to form an opinion within the meaning of Section 3(1) of the Act that the activities of HNLC continue to be detrimental to the peace and internal security of India and for fresh declaration of HNLC as an unlawful association for another two years.

19. The Secretary to the Government of Meghalaya, Political Department appearing as SW -1 :

- A. has deposed that HNLC through various Press releases has been calling for bandh and non-cooperation on every National Day celebrations i.e. Republic Day and Independence Day celebrations;
- B. has proved as Ex.SW -1/1 to SW -1/6 the Press reports, of calls given by Sh. Sainkupar Nongtraw, Publicity Secretary of HNLC on the occasion of Independence Day and Republic Day of India during the years 2009-2010, to protest against the celebration of the Indian National days "within the territory of Hynniewtrep Nation" for the reason that when India achieved its independence the "Standstill Agreement" assuring independence to Hynniewtrep people stood broken; he has further deposed that the said calls result in cancellation of trains etc.;
- C. has also proved the call given by HNLC for bandh to protest the visit of Home Minister of India to the State of Meghalaya on 19th December, 2009 for the reason of the Union Home Minister of India ruling the Hynniewtrep people through "illegal subjugation" in areas which were leased to the British for a long time and to protest against the forceful occupation by India of Hynniewtrep land;
- D. has deposed of the links of HNLC with ULFA, NDFB, NSCN(IM) & NLFT other unlawful associations;
- E. has also deposed that owing to the declaration of HNLC in the past as an unlawful association, the Police has been able to effectively curtail the activities of HNLC and which has also led to at least 180 members of HNLC to surrender;
- F. has deposed that unless the declaration of HNLC as an unlawful association is extended, the Police would be severely handicapped in further controlling the unlawful activities of HNLC.

20. Evidence of the activities of HNLC in the West Khasi Hills District of the State of Meghalaya has been given by Sh. Silvester Kharlyngdoh, Dy. Commissioner of the District appearing as SW-2, Dr. N. Rajamarthandan, Superintendent of Police of the District appearing as SW-3 and by Mr. Amit Raj Deep, Sub-Inspector of the District appearing as SW-12. They have :

- A. deposed that HNLC is still active in the District and engaging in illegal and extortion activities to raise the funds for its unlawful aims and objectives;
- B. deposed that HNLC has been subverting and disrupting the sovereignty and territorial integrity of India and extorting money from mostly in Pormodar, Nongjri and Borsora areas in the District.
- C. proved as Ex.SW-2/2 to Ex. SW-2/7 the FIRs of the illegal activities of the members/cadres of HNLC;
- D. proved as Ex.SW-2/9 the Press report of an e-mailed statement issued by Sh. Sainkupar Nongtraw, spokesperson of the HNLC to "fight with arms towards the freedom of Hynniewtrep people in the Hynniewtrep land";
- E. deposed that the bans are called to defy the sovereignty of India and create a fear psychosis in the population and to incite the people not to submit to the Government of India and to defy the Government of India;
- F. deposed that HNLC indulges in extortion of money from business communities to purchase arms for themselves to take up an armed rebellion to secede from the territory of India;
- G. deposed that HNLC cadres target those who abide by the laws of India, in an attempt to prevent them from obeying the laws of India;
- H. in response to Tribunal question, deposed that the FIRs proved by them were at the stage of investigation and sanction for prosecution.
- I. proved the FIRs of the offence of extortion by Shri Alex Hashah core member of HNLC and of his arrest along with eight supporters and a cache of arms, mobile phones with several sim cards;

- J. deposed that owing to the bandh calls given by HNLC, most people of the District anticipating trouble remain indoor and by repeatedly disrupting the National celebrations HNLC is endeavouring to achieve its objective of secession;
- K. deposed about the links and nexus of HNLC with NSCN (IM) and NLFT and that they together cause a serious threat to the sovereignty, territorial integrity and internal and external security of the country;
- L. have deposed that HNLC by indulging in such activities spreads a message that governance in the West Khasi Hills District is not by the Government of the State but by them and that the Government is unable to effect development in the region.

21. Evidence of the activities of HNLC in the East Khasi Hills District of the State of Meghalaya has been given by Sh. Jopthiaw Lyngdoh, Deputy Commissioner of the District appearing as SW-4, Mr. M. Kharkrang, Superintendent of Police of the District appearing as SW-5, Mr. Matiush Ch. Sangma, Sub-Inspector of the District appearing as SW-13 and Mr. Jeffrey W. Suting, Sub-Inspector of the District appearing as SW-14. They have:

- A. deposed about the unlawful, nefarious and anti-national activities of HNLC in the said District on the same lines as the witnesses aforesaid;
- B. deposed of the incident of two weeks prior to the date of deposition on 25th February, 2011 when five persons belonging to NDFB were apprehended in Ri-Bhoi District and during interrogation admitted their linkage to Mr. Bobby Marwein of HNLC hiding in Bangladesh;
- C. on the basis of records maintained in the said District deposed that HNLC is acting for independence of 'Hynniewtrep Land' with no connection with India and have proved as Ex.SW-5/2 a pamphlet circulated by HNLC in the District in February, 2009 in which HNLC has demanded freedom from Indian colonialism, imperialism and chauvinism and demanded a separate nation for Hynniewtrep people;
- D. proved the statement recorded on 20th May, 2009 of Sh. Phikerlang Majaw @ San, one of the cadres of HNLC who had surrendered. As per the said statement, there were 200 cadres of HNLC and who were trained in foot and arms drills, handling of arms like AK-47, SLR, 303 rifles etc. and camps of HNLC in Chittagong Hill Tract together with the camps of other unlawful/terrorist organizations like NDFB, NLFT, KYKL;
- E. proved as Ex.SW-5/4, the statement recorded on 7th August, 2009 of another HNLC cadre member viz. Sh. Imlang Byrjuh Marwein @ Small who had also surrendered in the East Khasi Hills District. He has also deposed about the training camps held by HNLC for its cadres to teach them to handle arms like AK-47, Sniper Rifle, 303 Rifle and of collecting money from the villagers of Nongsteng and Mawphew for onward transmission to HNLC cadres in Bangladesh;
- F. proved the FIRs Ex.SW-5/6, Ex.SW-5/7, Ex.SW-5/8 & Ex.SW-5/9 registered in December, 2009 and May, 2010 with respect to the offences of extortion, causing grievous hurt against HNLC cadre members;
- G. proved the bandh calls otherwise given by HNLC cadres in the District;
- H. deposed of having learnt on the basis of intelligence inputs, of HNLC still maintaining good relations with other anti-national insurgent groups of the States of North Eastern India like the United Liberation Front of Asom (ULFA), the National Socialist Council of Nagalim (NSCN), the National Democratic Front of Bodoland (NDFB) and the National Liberation Front of Tripura (NLFT);
- I. deposed that the principle object of HNLC is to form a sovereign 'Khasi Hills State' independent of the Union of India and of the offences being committed by its members to collect money for achieving the said object and to subvert the sovereignty of India;
- J. deposed that a few days before the deposition on 25th February, 2011, HNLC had given a demand note for Rs. 50,00,000/- to one of the civilians in the District;
- K. on Tribunal question, informed that action on the basis of FIRs registered was being taken and in one case charge sheet had been filed and the other cases were at the stage of investigation.

22. Evidence of the activities of HNLC in the Jaintia Hills District of the State of Meghalaya has been given by Mr. T. Dkhar, Deputy Commissioner of the District, appearing as SW-6, Mr. O. Passi, Superintendent of Police of the District appearing as SW-7 and Mr. Q.E. Paik, Sub-Inspector of the District appearing as SW-15. They have:

- A. similarly deposed of HNLC being still active;
- B. proved the FIR dated 5th August, 2010 with respect to the offences committed by HNLC and its cadres as Ex. SW-6/2;
- C. in response to the Tribunal question, deposed that HNLC calls bandh to stop the people from celebrating days of national importance in India and the said bandh calls did meet with partial success;
- D. deposed of arrest of two members of HNLC who were attempting to enforce the bandh call given on the occasion of Republic Day of the year 2011 ;
- E. deposed that the main objective of HNLC was secession from India;
- F. deposed of recovery of huge quantity of arms to be used to disturb the Independence Day celebrations and proved the seizure memo and the statement recorded of the accused in this regard.

23. Evidence of the activities of HNLC in the Ri-Bhoi District of the State of Meghalaya has been given by Mr. Mawshan Kharmujai, Deputy Commissioner of the District appearing as SW-8, Mr. Smti.C.A. Lyngwa, Superintendent of Police of the District appearing as SW-9, Mr. M. Koch, Sub-Inspector of Police of the District appearing as SW-10 and Mr. E.D. Manar, Sub-Inspector of the District appearing as SW-11. They have :

- A. proved arrest on 4th September, 2010 of Mr. Emanson Maring @ Freddy @ Bah Hep and the statement made by him during interrogation of the training camps for HNLC cadre in weaponry and of hiding in Bangladesh after committing offences in India and of the meeting held of HNLC cadres in Bangladesh during the month of December, 2010/first week of January, 2011 and of joint operations of HNLC with NDFB;
- B. proved as Ex. SW-10/2 the FIR dated 10th February, 2011 and proved the statement made by Mr. Lachit Boro as Ex. SW-10/6. The said Mr. Lachit Boro has similarly deposed of the anti-national activities of HNLC of which he was a cadre member;
- C. proved as SW-11/13 the FIR dated 15th February, 2011 and also proved the statements of the arrested cadres of HNLC and a reading whereof similarly proves the anti-national activities indulged by HNLC members.

24. On the basis of the aforesaid material and evidence, it has to be adjudicated whether the opinion formed by the Government of India is justified or not and whether the Notification declaring HNLC as an unlawful association is tenable in law and whether to confirm the declaration or cancel it.

25. The nature of these proceedings and the procedure to be applied therein has been discussed in detail in paras 85 to 88 of the Report dated 14th May, 2007 of the Tribunal constituted earlier in pursuance to the earlier Notification under the Act with respect to HNLC and as such need is not felt to reiterate the position in law. It was concluded that inherently the proceedings are not in the nature of the trial and the Tribunal is to only enquire broadly whether an Association has to be declared as unlawful. Reliance was placed on *Jamaat-E-Islami Hind Vs. Union of India* (1995) 1 SCC 428 to observe that the Tribunal's procedure should be fair and reasonable because its decision has the likelihood of restraining the fundamental right to association though for a limited period. It was held that the adjudicatory process required to be followed is not a trial and the procedure has to be like an enquiry aimed at gathering material needed to form a conclusion. Qua procedure, it was held that as far as possible, the provisions of the Indian Evidence Act, 1872 have to be followed, however having regard to the nature of the proceedings and likelihood of sensitive nature of material likely to be disclosed during the proceedings before it, the Tribunal is not hidebound by rules of evidence and has to follow them in spirit.

26. The definition of unlawful activities under Section 2(o) of the Act was amended so as to incorporate (i), (ii) and (iii) and by addition of the expression "or". The amendment of this definition clause has significantly changed the scope of the expression 'unlawful activity'. In the pre-amended definition clause, both the ingredients of (i) and (ii) ought to be satisfied while under the amended clause, in the event either of the three clauses mentioned under Sub-section (o) of Section 2 are satisfied, it would be an 'unlawful activity'. "Any individual or association" "which causes or is intended to cause disaffection against India", would be an "Individual" or an "association" involved in an unlawful activity. "Disaffection" has been explained to be including disloyalty and all feelings of enmity. It is the species of disaffection and people are disaffected to the Government. In simple words, it is a manner of challenging the administration by unlawful means. In giving this expression a wide meaning, a Bench of Calcutta High Court in the case of "Saptaha" a Bengali B-Weekly Newspaper and in the matter of Benoy Chattopadhyaya AIR 1950 Calcutta 445 held as under :

"The word 'disaffection' signifies political alienation or discontent, that is to say, a feeling of disloyalty to the existing Government, which tends to a disposition not to obey, but to resist and subvert the Government."

27. Section 2(p) defines 'unlawful association' as any association "which has for its object any unlawful activity, or which encourages or aids persons to undertake any unlawful activity, or of which the members undertake such activity". The Legislature intended to give this defining sub-section a wider meaning and interpretation, that is the precise reason as to why words like "encourages", "aids" have been used in the Section. Even if an association has for its objective any activity which is punishable under Section 153A or 153B of the Indian Penal Code, or the members of which undertake such activity, would be an 'unlawful association'. There is no occasion for the Tribunal to give it a restricted interpretation/meaning. In any case, the afore-noted activities of HNLC are an open challenge to the sovereign power of the State, their unlawful activities including causing fear psychosis in the minds of the public, by extortion of money, abduction, murder and attack on security forces and interference with exploitation of mineral wealth are the clear indications of the attempt on the part of these associations to hinder the State Administration by unlawful and illegal means. HNLC is found to be still i.e. after the last Notification of the year 2008 involved in disrupting sovereignty and integrity of India, procuring of weapons, infringing the borders of the Union of India, keeping their contacts with other banned organizations and unlawful associations in and outside the territorial limits of Indian Territory.

28. In the case of *Union of India and Ors. Vs. Sukumar Sengupta & Ors.* AIR 1990 SC 1692 sovereignty was described by the Court as a quality of right, a bundle of rights and that it depends on the facts and circumstances of each case. The complexities of modern developed societies need amicable and peaceful settlement of national and international disputes and the expression sovereignty and independence had to be modified, keeping in view the developments. It being a bundle of rights, obligation of the State to protect members of its Society is placed on a higher pedestal. Casual principles of settled law thus, require the interpretation of unlawful assemblies and unlawful activities in that direction. If the members of such unlawful association terrorize the common man on the road and create a law and order problem for normal administration by the different State organs with the aims aforesaid, would not only be intending but actually disrupting the sovereignty and territorial integrity of India.

29. Explaining the importance of the concept of sovereignty, the Supreme Court in the case of *Synthetics and Chemicals Ltd. and Ors. vs. State of U.P. and Ors.* (1990) 1 SCC 109, held that "it is the exercise of sovereign power which gives the State sufficient authority to enact any law subject to the limitations of the Constitution to discharge its functions. The Indian State, between the Centre and the States, has sovereign power. The Sovereign power is plenary and inherent in every sovereign State to do all things which promote the health, peace, morals, education and good order of the people. This power of sovereignty is, however, subject to Constitutional Limitations."

30. The above enunciated principles of law indicate that the expression "sovereignty" is to be given a meaning which is understood in common parlance and is certainly an expression of wide dimensions. The object of power of sovereignty is ultimately for the welfare of the people of the State. So to perform its functions of that kind without disruption, unlawful impediments and threat from an association or a group of persons would infringe the very basic fundamentals of democratic system.

31. The depositions of all the witnesses on behalf of State of Meghalaya show that HNLC continues to be active and functions in East and West Khasi Hills Districts, Jaintia Hills District and Ri- Bhoi District. According to the witnesses on behalf of the State of Meghalaya, it also maintains active links with banned organizations such as NSCN, ULFA, NDFB, KNV and NLFT etc. There have been some incidents where HNLC's cadres were arrested or surrendered which led to recovery of weapons. The evidence further points to HNLC holding out threats to the people in 2009 and 2010 and preventing them from participating in national celebrations for Republic Day and Independence Day. Additionally, the witnesses deposed that HNLC wants a separate State for Hynniewtrep People outside the territory of India. According to these witnesses, who include the Deputy Commissioners, Superintendent of Police and the Investigation Officers of the FIRs registered with respect to unlawful activities of HNLC of the four Districts, the top leadership of HNLC is based outside the Indian boarder, in Bangladesh, HNLC also seeks the help of other associations declared unlawful for training and resource building etc.

32. The analysis of unrebutted evidence shows that HNLC is an organization committed to achieving a separate or independent State for the Hynniewtrep people outside India and to that end it seeks to achieve the objective through acts of violence. These acts of violence include attacks on police personnel, use of sophisticated and illegal weapons, repeated acts exhorting the people not to attend national day celebrations, etc. The evidence also points to HNLC maintaining contacts and link with other organizations that have been declared unlawful or as Terrorist Organizations under Section 2(p) (m) and Section 35 of the Act, in the Schedule to the Act. Its leadership is in Bangladesh where they have camps to train cadres and where apparently they flee after committing acts of kidnapping, extortion and other acts of violence.

33. A common thread appears to run through evidence led with respect to the four Districts - the objective appears to be to intimidate the people, disrupt normal functioning and undermine economic activity through extortions and kidnapping. The incidents where repeatedly HNLC has held out threats against people to prevent and intimidate them from

participating in national day celebrations coupled with declaring the mineral wealth of the country namely Uranium as belonging to Hynniewtrep people, display its commitment to pursue the path of violence to achieve the end of a separate State through armed struggle and violence. This clearly establishes that its activities do not have any lawful aim but are meant to undermine and disrupt the sovereignty and territorial integrity of India.

34. On the basis of the evidence led and material placed on record, I am satisfied that HNLC carries on unlawful activities which are detrimental and intended to disrupt the territorial integrity of India. I am further satisfied that notwithstanding the arrest and surrender of several of the cadre members of HNLC, it continues to be active and engaged in disruptive activities detrimental to the territorial integrity of India.

35. In view of the above discussion and after considering all the materials on record, this Tribunal is of the opinion that sufficient materials have been shown by the Union of India and the State of Meghalaya to confirm the Notification under Section 3(1).

36. I am therefore of the considered view that sufficient cause exists for declaring HNLC as an unlawful association. Accordingly, in accordance with Section 4(3) of the Act, this Tribunal hereby confirms the Notification No. 2792(E) dated 16th November, 2010 declaring 'Hynniewtrep National Liberation Council' as unlawful Association in tenus of Section 3(1) of the Act.

37. The entire record of the proceedings of the Tribunal, including the sealed envelope which has been re-sealed, be submitted along with this order to the Central Government.

JUSTICE RAJIV SAHAJENDLAW,
Unlawful Activities (Prevention) Tribunal

Dated : 13th May, 2011.